Impact Factor (SJIF): 5.158 E-ISSN: 2583-7206

International Journal of All Subject Research

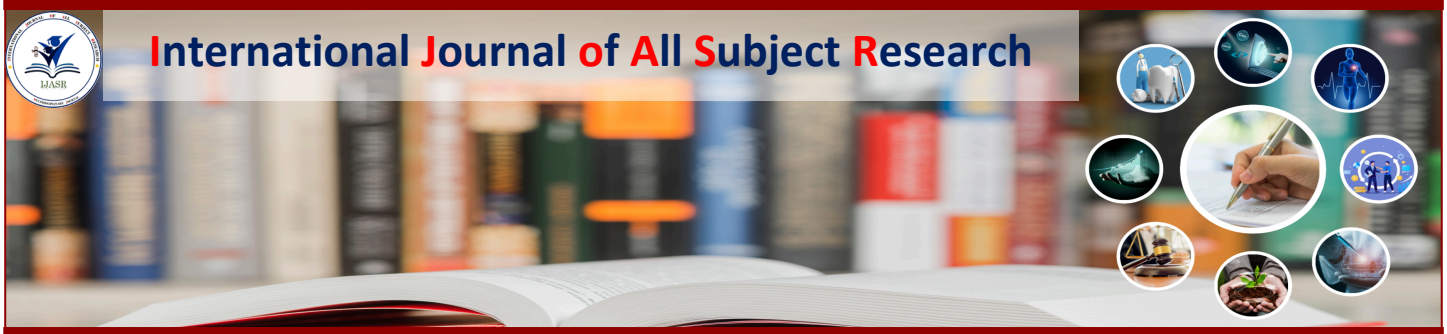

Received: 16/November/2023 **IJASR:** 2024; 3(1):39-42 **Accepted:** 22/January/2024

वैश्विक शासन में सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों का अंतर्संबंध

[1]डॉ. राम दर्शन फोगाट और [*2]पाटील विशाल भानुदास

[1]रिसर्च स्कॉलर, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत।

[*2]एसोसिएट प्रोफेसर, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत ।

सारांश

सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बीच संबंध वैश्विक शासन में सबसे विवादास्पद बहसों में से एक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तर्क है कि मानवाधिकारों को प्रत्येक संस्कृति के मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जबकि सार्वभौमिक मानवाधिकार ढांचे का मानना है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी व्यक्ति समान मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। यह शोधपत्र सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बीच के अंतरसंबंध की खोज करता है, वैश्विक शासन में इन दो अवधारणाओं के मिलने पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों की जांच करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे, सांस्कृतिक प्रथाओं और केस स्टडीज के विश्लेषण के माध्यम से, शोधपत्र जांच करता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद को सार्वभौमिक मानवाधिकारों की आवश्यकता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है और क्या वैश्विक शासन संरचनाएं दोनों दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकती हैं।

मुख्य शब्दः मानव अधिकार और सांस्कृतिक सापेक्षवाद।

प्रस्तावना

मानवाधिकारों की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होलोकॉस्ट और उपनिवेशवाद जैसे वैश्विक अत्याचारों के जवाब के रूप में उभरी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) ने यह विचार प्रस्तुत किया कि सभी मनुष्यों को राष्ट्रीयता, संस्कृति या धर्म की परवाह किए बिना मौलिक अधिकारों के एक समूह का हकदार होना चाहिए। यह सिद्धांत आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन और वैश्विक शासन को रेखांकित करता है।

हालाँकि, सार्वभौमिक मानवाधिकारों का विचार अक्सर सांस्कृतिक सापेक्षवाद से टकराता है, जो मानता है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्रत्येक संस्कृति के मानदंडों, प्रथाओं और मूल्यों के अनुसार समझा और व्याख्या किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद इस विचार को चुनौती देता है कि मानवाधिकारों का एक एकल, सार्वभौमिक मानक सभी समाजों में लागू किया जा सकता है, यह तर्क देते हुए कि ऐसा ढांचा अक्सर वैश्विक परंपराओं की विविधता को समायोजित करने के बजाय प्रमुख या पश्चिमी संस्कृतियों के मूल्यों को दर्शाता है।

इस तनाव का वैश्विक शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जबकि मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय निकाय सार्वभौमिक मानकों की वकालत करते हैं, कई देश और संस्कृतियाँ इन मानकों का विरोध करती हैं, उनका दावा है कि वे स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखने में विफल हैं। इस प्रकार प्रश्न यह बन जाता है: सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध दुनिया में सार्वभौमिक मानवाधिकारों को कैसे बढ़ावा दिया और संरक्षित किया जा सकता है? यह पत्र सांस्कृतिक सापेक्षतावाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रतिच्छेदन की जांच करता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि वैश्विक शासन संस्थाएँ इन प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों को नेविगेट करती हैं।

***Corresponding Author:** पाटील विशाल भानुदास

1. सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानव अधिकारों को परिभाषित करना

क. सांस्कृतिक सापेक्षवाद: सांस्कृतिक सापेक्षवाद, एक दार्शनिक और मानवशास्त्रीय अवधारणा के रूप में, इस बात पर जोर देता है कि मूल्यों और प्रथाओं को उनके विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह मानता है कि किसी भी संस्कृति के मानदंड स्वाभाविक रूप से किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों से बेहतर नहीं हैं। जब मानवाधिकारों पर लागू किया जाता है, तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद इस धारणा को चुनौती देता है कि सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्थानीय रीति–रिवाजों और परंपराओं पर विचार किए बिना सभी समाजों पर लागू किया जा सकता है।

सांस्कृतिक सापेक्षवाद के मुख्य समर्थक, जैसे मानवविज्ञानी रूथ बेनेडिक्ट और मेलविल हर्सकोविट्स, तर्क देते हैं कि नैतिक प्रणालियाँ सार्वभौमिक नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, बहुविवाह, महिला खतना या जाति व्यवस्था जैसी प्रथाएँ, जबकि कुछ संस्कृतियों में विवादास्पद हैं, उनके सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर दूसरों में वैध हो सकती हैं।

ठ. सार्वभौमिक मानव अधिकार: सार्वभौमिक मानवाधिकार, जैसा कि यूडीएचआर और उसके बाद की मानवाधिकार संधियों में व्यक्त किया गया है, यह दावा करता है कि सभी लोग, अपनी मानवता के आधार पर, अविभाज्य अधिकारों के एक समूह के हकदार हैं। इन अधिकारों को राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भ से परे, मानवीय गरिमा के लिए अंतर्निहित माना जाता है। उदाहरण के लिए, यूडीएचआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और यातना से सुरक्षा जैसे अधिकारों की गारंटी देता है।

जबकि सार्वभौमिक मानवाधिकारों के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्यापक रूप से अपनाया गया है, उनके कार्यान्वयन को अक्सर सांस्कृतिक मतभेदों के कारण प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। आलोचकों का तर्क है कि मानवाधिकार ढांचा पश्चिमी मूल्यों को दर्शाता है, जो सामुदायिक या सामूहिक अधिकारों पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है, और अक्सर शासन और न्याय की गैर–पश्चिमी प्रणालियों के साथ संघर्ष करता है।

साहित्य की समीक्षा

सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बीच तनाव पर अकादमिक चर्चा में व्यापक रूप से बहस हुई है, खासकर वैश्विक शासन के संदर्भ में। रूथ बेनेडिक्ट (1934) और मेलविले हर्सकोविट्स (1955) जैसे मानवविज्ञानियों द्वारा पहली बार व्यक्त किए गए सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सुझाव है कि मूल्यों और प्रथाओं को उनके सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए, बाहरी मानदंडों को लागू करने के खिलाफ तर्क देते हुए। इसके विपरीत, सार्वभौमिक मानवाधिकार–जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) में औपचारिक रूप दिया गया है– अविभाज्य अधिकारों की वकालत करते हैं जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

मैरी (2006) और डोनेली (2003) जैसे विद्वान इन दृष्टिकोणों के बीच अंतर्निहित तनाव पर जोर देते हैं, खासकर जब सांस्कृतिक प्रथाएँ– जैसे कि लैंगिक असमानता, महिला जननांग विकृति, या बाल विवाह– अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के साथ टकराव करती हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सार्वभौमिक मानवाधिकार अक्सर पश्चिम–केंद्रित होते हैं और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखने में विफल होते हैं, जिससे गैर–पश्चिमी देशों से प्रतिरोध होता है (तासियोलास, 2021)। अन्य, जैसे कि सिकिंक (2020), अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की वकालत करते हैं जहाँ सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाता है, लेकिन मूल मानवाधिकार, जैसे कि जीवन का अधिकार और यातना से मुक्ति, गैर–परक्राम्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसी वैश्विक शासन संस्थाएँ इन तनावों को दूर करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, जो अक्सर सांस्कृतिक संप्रभुता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करती हैं। ग्लोबल साउथ अक्सर मानवाधिकार ढाँचों को नव–औपनिवेशिक औजारों के रूप में देखता है, जो सार्वभौमिक मानदंड बनाने के प्रयासों को और जटिल बनाता है (फॉक, 2019; ज्वार्ट, 2022)।

शोध के उद्देश्य

1. वैश्विक दक्षिण में मानवाधिकार विमर्श को आकार देने में सांस्कृतिक सापेक्षवाद की भूमिका की जांच करना
2. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और वैश्विक शासन ढांचे के साथ सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अनुकूलता का विश्लेषण करना

क्रियाविधि

यह अध्ययन वैश्विक शासन में सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानव अधिकारों के बीच अंतःक्रिया का पता लगाने के लिए सैद्धांतिक कानूनी अनुसंधान, केस अध्ययन और सामग्री विश्लेषण को मिलाकर एक गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करेगा।

1. **सैद्धांतिक कानूनी अनुसंधान:** प्रमुख मानवाधिकार दस्तावेजों (जैसे, यूडीएचआर, आईसीसीपीआर) के विश्लेषण से यह आकलन किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सार्वभौमिक अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है।
2. **केस स्टडीज:** लैंगिक असमानता (जैसे, बाल विवाह, महिला जननांग विकृति) और स्वदेशी अधिकारों पर चयनित केस स्टडीज स्थानीय सांस्कृतिक मानदंडों और सार्वभौमिक मानवाधिकार मानकों के बीच व्यावहारिक संघर्षों को दर्शाएंगी। ये केस स्टडीज उन

क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगी जहाँ सांस्कृतिक सापेक्षतावाद सीधे तौर पर मानवाधिकारों को चुनौती देता है, जैसे कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्से।

3. **विषय–वस्तु विश्लेषण:** नीति दस्तावेजों, अंतरराष्ट्रीय संधियों और वैश्विक संस्थाओं (जैसे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल) के भाषणों की गुणात्मक समीक्षा से विश्लेषण होगा कि मानवाधिकार चर्चाओं में भाषा और रूपरेखा किस प्रकार सांस्कृतिक मतभेदों को प्रभावित करती है।
4. **विशेषज्ञ साक्षात्कार (वैकल्पिक):** मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सांस्कृतिक राजनयिकों और विद्वानों के साथ साक्षात्कार से विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि मिलेगी कि वैश्विक शासन संरचनाएं इन चुनौतियों का समाधान कैसे करती हैं।

परिणाम और चर्चा

1. सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बीच तनाव

सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बीच बहस कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के केंद्र में है। ये तनाव लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों में सबसे अधिक स्पष्ट हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को सार्वभौमिक मानवाधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते समय कई प्रमुख चुनौतियाँ सामने आती हैं:

क. मानवाधिकार और लैंगिक समानता

संघर्ष के सबसे अधिक दिखाई देने वाले क्षेत्रों में से एक महिलाओं के साथ व्यवहार है, जहाँ कई गैर–पश्चिमी संस्कृतियों में लिंग भूमिकाओं के संबंध में अलग–अलग मानदंड हैं। बाल विवाह, महिला जननांग विकृति (FGM) और महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसी प्रथाओं ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अभियानों को जन्म दिया है। हालाँकि, कुछ सांस्कृतिक सापेक्षवादियों का तर्क है कि ये प्रथाएँ सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से अंतर्निहित हैं और उन्हें किसी बाहरी मानक से नहीं आंका जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, कुछ लोग तर्क देते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की पश्चिमी धारणाएँ, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वायत्तता पर जोर देने वाली धारणाएँ, उन समाजों में अनुपयुक्त हो सकती हैं जहाँ समुदाय और पारिवारिक दायित्व प्राथमिकता रखते हैं। इससे यह सवाल उठता है: क्या सार्वभौमिक मानवाधिकार अभियान उन प्रथाओं को संबोधित कर सकते हैं जिन्हें संस्कृति के जीवन के तरीके के रूप में देखा जाता है, या उन्हें स्थानीय सांस्कृतिक मानदंडों के अनुकूल होना चाहिए?

बी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ईशनिंदा कानून

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक और विवादास्पद मुद्दा है। कई मुस्लिम बहुल देशों में, ईशनिंदा कानून धार्मिक विश्वासों की आलोचना करने वाले भाषणों पर रोक लगाते हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकारों के परोपकारो का तर्क है कि ये कानून मुक्त भाषण और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के समर्थकों का कहना है कि इन समाजों में सामाजिक सद्भाव और धर्म के प्रति सम्मान की रक्षा के लिए ऐसे कानून आवश्यक हैं।

चार्ली हेब्दो का मामला, जहाँ व्यंग्य पत्रिका पर पैगंबर मुहम्मद के कार्टून प्रकाशित करने के लिए हमला किया गया था, सार्वभौमिक मानवाधिकारों (स्वतंत्र अभिव्यक्ति) और धर्म और सम्मान के संबंध में सांस्कृतिक मानदंडों के बीच टकराव का उदाहरण है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सार्वभौमिक मानकों को लागू किया जाना चाहिए, जबकि अन्य का तर्क है कि ऐसे मानदंडों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए।

सी. स्वदेशी अधिकार और भूमि संप्रभुता

स्वदेशी समुदायों को अक्सर अपने सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, जबरन आत्मसात करना और भेदभाव। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों ने स्वदेशी अधिकारों को मान्यता देने में प्रगति की है, लेकिन इन अधिकारों का अनुप्रयोग राष्ट्रीय सरकारों या बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास लक्ष्यों से टकरा सकता है। उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचे का निर्माण या स्वदेशी भूमि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आर्थिक विकास के लिए सरकारों द्वारा उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन स्वदेशी समुदाय ऐसी कार्रवाइयों को भूमि, संस्कृति और स्वायत्तता के अपने अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख सकते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवादियों का तर्क है कि स्वदेशी संस्कृतियों को अपनी परंपराओं और जीवन के तरीकों को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही वे आधुनिक वैश्विक शासन संरचनाओं के साथ रेखित न हों। इसके विपरीत, सार्वभौमिक मानवाधिकारों के पैरोकार इस बात पर जोर देते हैं कि सभी लोगों को बुनियादी मानवीय गरिमा का अधिकार होना चाहिए, जिसमें भूमि और सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार भी शामिल है।

2. इन तनावों को सुलझाने में वैश्विक शासन की भूमिका

वैश्विक शासन संस्थाएँ, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय मानवाधिकार निकाय, इन प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों को समेटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि यूडीएचआर सार्वभौमिक मानदंड स्थापित करता है, यह सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक संदर्भों पर विचार करने की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है। यह नाजुक संतुलन अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाए गए कई दृष्टिकोणों में परिलक्षित होता है:

क. संयुक्त राष्ट्र और सांस्कृतिक संवेदनशीलता: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, सार्वभौमिक मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देते हुए, मानवाधिकार उल्लंघनों को

संबोधित करने में सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को पहचानती है। उदाहरण के लिए, यूनेस्को सांस्कृतिक विविधता और अंतर–सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने पर जोर देता है, यह सुझाव देते हुए कि सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति सम्मान मानवाधिकारों की सुरक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए।

हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि इस सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बावजूद, कई मानवाधिकार तंत्र अभी भी पश्चिमी आदर्शों को दर्शाते हैं, जो सभी सांस्कृतिक संदर्भों में पूरी तरह से लागू या स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर–औपनिवेशिक संदर्भों में मानवाधिकार मानकों के अनुप्रयोग से अक्सर तनाव पैदा होता है, क्योंकि कई देश इन ढाँचों को पश्चिमी औपनिवेशिक प्रभाव के अवशेष के रूप में देखते हैं।

बी. सार्वभौमिक अधिकारों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की चुनौती: जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून और सम्मेलन सार्वभौमिक मानवाधिकारों की वकालत करते हैं, स्थानीय स्तर पर इन अधिकारों का कार्यान्वयन सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं के कारण जटिल हो सकता है। गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को अक्सर उन क्षेत्रों में सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धांतों को बढ़ावा देने में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जहां मजबूत सांस्कृतिक परंपराएं उन सिद्धांतों के साथ संघर्ष करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे अपराधों के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना चाहता है, लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में इसके हस्तक्षेप को अक्सर संदेह के साथ देखा जाता है। कुछ मामलों में, देशों ने प्ब्ब् से यह दावा करते हुए खुद को अलग कर लिया है कि यह अफ्रीकी नेताओं को असंगत रूप से निशाना बनाता है और स्थानीय परंपराओं और कानूनी प्रणालियों की अवहेलना करता है।

3. सुलह के संभावित रास्ते

यद्यपि सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बीच तनाव असंगत प्रतीत हो सकता है, फिर भी ऐसे मार्ग हैं जिनके माध्यम से दोनों अवधारणाएं सह–अस्तित्व में रह सकती हैं और वैश्विक शासन को सूचित कर सकती हैं:

क. संवाद और पारस्परिक सम्मान: एक रास्ता वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना है जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक संदर्भों के महत्व दोनों को स्वीकार करता है। इस तरह के संवाद से ऐसे समझौते हो सकते हैं जो मौलिक मानवाधिकार मानकों को कायम रखते हुए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं। इस दृष्टिकोण को वैश्विक संस्थानों द्वारा सुगम बनाया जा सकता है जो अंतर–सांस्कृतिक समझ और आपसी सम्मान पर जोर देते हैं।

बी. संदर्भ–विशिष्ट दृष्टिकोण: संदर्भ–विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना है जो मानवाधिकार वकालत को स्थानीय सांस्कृतिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढालता है। उदाहरण के लिए, सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण लागू करने के बजाय, वैश्विक संस्थाएँ स्थानीय नेताओं और समुदायों के साथ मिलकर मानवाधिकारों की व्याख्या ऐसे तरीकों से कर सकती हैं जो सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संरेखित हों और सार्वभौमिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों का अंतसंबंध वैश्विक शासन के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। जबकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद स्थानीय सांस्कृतिक मानदंडों की प्रधानता के लिए तर्क देता है, सार्वभौमिक मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा पर जोर देते हैं। इन दृष्टिकोणों को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक बातचीत, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और ऐसी नीतियों के विकास की आवश्यकता होती है जो मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा करते हुए मानवीय अनुभवों की विविधता को पहचानती हों। सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बारे में चल रही बहस वैश्विक शासन के भविष्य को आकार देने के लिए आवश्यक है, और यह इस बात को प्रभावित करना जारी रखेगी कि विविधतापूर्ण दुनिया में मानवाधिकारों को कैसे समझा, लागू और संरक्षित किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. मेरी, एस.ई. (2006). मानवाधिकार और लैंगिक हिंसा: अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्थानीय न्याय में अनुवाद । यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।
2. डोनेली, जे. (2003). सिद्धांत और व्यवहार में सार्वभौमिक मानवाधिकार (दूसरा संस्करण). कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. नुसबाम, एम. (1999). महिलाएँ और मानव विकास: क्षमता दृष्टिकोण. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
4. सेन, ए. (2004). न्याय का विचार. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
5. यूनेस्को (2015)। जैव नैतिकता और मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा। न्छम्ब्ब्वतह से लिया गया।
6. पैसिक, एन. (2021)। सांस्कृतिक सापेक्षवाद और मानवाधिकार: एक समकालीन परिप्रेक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स, 25(4), 500–518।
7. तसियोलास, जे. (2021)। मानवाधिकार और सार्वभौमिकता: एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। एम.ई. गुडहार्ट (एड.), द रूटलेज हैंडबुक ऑफ ह्यूमन राइट्स (पृष्ठ 222–240) में। रूटलेज।
8. डोनेली, जे. (2020). सिद्धांत और व्यवहार में सार्वभौमिक मानवाधिकार (तीसरा संस्करण). कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. ज्वार्ट, टी. (2022). बदलती दुनिया में मानवाधिकार: एक सांस्कृतिक सापेक्षतावादी परिप्रेक्ष्य. यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, 33(2), 389–408.